

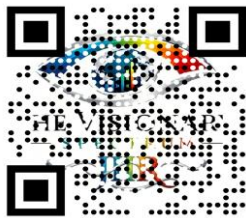
स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का भारत में रोजगार और नवाचार पर प्रभाव

डॉ. रमेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय बगली पिजड़ा मऊ

Email: kanakprakashan@gmail.com



Received 05 June 2026

Accepted 15 June 2026

Published 25 June 2026

Corresponding Author:

डॉ. रमेश कुमार

Email: kanakprakashan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/tvsjir.v1i2.05>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश:

पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। स्टार्टअप अब केवल सूचना प्रौद्योगिकी अथवा ई-कॉमर्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, वित्तीय तकनीक, अंतरिक्ष, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। इससे स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का प्रभाव रोजगार सृजन, उद्यमिता, तकनीकी नवाचार, नए उत्पादों के विकास तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान तक विस्तृत हुआ है। भारत सरकार के अनुसार 31 मार्च 2026 तक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.23 लाख से अधिक हो चुकी थी और इन स्टार्टअप द्वारा 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की सूचना दी गई थी। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता मिली और इनके द्वारा 4.99 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज किए गए। जून 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.3 लाख से अधिक हो चुकी थी और लगभग आधे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर-दो तथा टियर-तीन शहरों से जुड़े बताए गए।

नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा, जबकि 2020 में भारत 48वें स्थान पर था। भारत निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर रहा और उसके चार नवाचार समूह—बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई—विश्व के शीर्ष 100 नवाचार समूहों में सम्मिलित हुए। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक स्टार्टअप द्वारा 19,400 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए जा चुके थे। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है। इसमें DPIIT, आर्थिक सर्वेक्षण, Startup India, WIPO तथा अन्य आधिकारिक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्टार्टअप अर्थव्यवस्था भारत में रोजगार तथा नवाचार का महत्वपूर्ण स्रोत बन रही है, किंतु पूँजी की असमान उपलब्धता, स्टार्टअप विफलता, अनुसंधान एवं विकास पर कम व्यय, कौशल-अंतर, क्षेत्रीय असमानता और रोजगार की गुणवत्ता जैसी चुनौतियों पर ध्यान दिए बिना इसका पूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।

प्रमुख शब्द: स्टार्टअप, रोजगार, नवाचार, उद्यमिता, Startup India, पेटेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय तकनीक, नया रोजगार, भारतीय अर्थव्यवस्था।

1. प्रस्तावना

आर्थिक विकास के पारंपरिक मॉडल में बड़े उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और स्थापित निजी कंपनियाँ रोजगार तथा उत्पादन के मुख्य स्रोत माने जाते थे। इक्कीसवीं शताब्दी में तकनीकी परिवर्तन, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जोखिम पूँजी के विस्तार ने एक नई उद्यमशील अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इस अर्थव्यवस्था में छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने की क्षमता रखने वाली कंपनियाँ नई समस्याओं का समाधान खोजती हैं, तकनीक का व्यावसायिक उपयोग करती हैं और नए बाजार विकसित करती हैं। इन्हीं उद्यमों को सामान्यतः स्टार्टअप कहा जाता है।

भारत में स्टार्टअप गतिविधियाँ पहले भी मौजूद थीं, किंतु 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई Startup India पहल ने इसे एक स्पष्ट नीतिगत ढाँचा प्रदान किया। इसका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ऐसे उद्यमों को विकसित करना था जो भविष्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं रोजगार अवसर पैदा कर सकें। Startup India कार्ययोजना में सरल नियम, वित्तीय सहायता, कर प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा संरक्षण, सरकारी खरीद में अवसर और उद्योग-अकादमिक सहयोग जैसे तत्व सम्मिलित किए गए।

इसके परिणामस्वरूप स्टार्टअप की अवधारणा केवल बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रही। छोटे शहरों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और क्षेत्रीय उद्यमियों की भागीदारी भी बढ़ी। जून 2026 से संबंधित सरकारी विवरण के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.3 लाख से अधिक हो चुकी थी और लगभग 50 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर-दो और टियर-तीन शहरों से जुड़े थे।

इस विस्तार ने दो प्रश्नों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है—पहला, क्या स्टार्टअप वास्तव में भारतीय युवाओं के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं? दूसरा, क्या स्टार्टअप अर्थव्यवस्था भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता रहने के बजाय नवाचार और नई तकनीकों का उत्पादक बनाने में योगदान दे रही है? प्रस्तुत शोध-पत्र इन्हीं दोनों पक्षों का विश्लेषण करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप अर्थव्यवस्था के रोजगार एवं नवाचार संबंधी प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की प्रकृति, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, महिलाओं और छोटे शहरों की भागीदारी, पेटेंट एवं तकनीकी नवाचार, अनुसंधान के व्यावसायीकरण तथा सरकारी नीतियों की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही स्टार्टअप क्षेत्र में पूँजी, कौशल, अनुसंधान, रोजगार की स्थिरता और व्यवसाय विफलता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया है।

3. शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अध्ययन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, DPIIT, Startup India, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के Global Innovation Index 2025 और सरकारी बौद्धिक संपदा आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

रोजगार से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण करते समय यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है कि DPIIT द्वारा प्रकाशित कई रोजगार आँकड़े मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित हैं। इसलिए उन्हें संपूर्ण भारतीय श्रम बाजार के सत्यापित पेरॉल आँकड़ों के समान नहीं माना जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी देश में पेटेंट संख्या अथवा स्टार्टअप संख्या में वृद्धि अपने-आप नवाचार की गुणवत्ता का पूर्ण प्रमाण नहीं होती। अतः अध्ययन में मात्र संख्या के साथ व्यापक आर्थिक संदर्भ को भी ध्यान में रखा गया है।

4. भारत में स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का विस्तार

वर्ष 2016 में Startup India कार्यक्रम प्रारंभ होने के समय DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बहुत कम थी। 2025 के अंत तक इसमें असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। 31 दिसंबर 2025 तक DPIIT ने 2,07,135 स्टार्टअप को मान्यता दी थी। वर्ष 2016 में जहाँ 502 इकाइयों को मान्यता मिली थी, वहीं 2025 में एक ही कैलेंडर वर्ष के दौरान 49,429 इकाइयों को मान्यता मिली।

इसके बाद भी विस्तार जारी रहा। 31 मार्च 2026 तक कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.23 लाख से अधिक हो गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली, जो Startup India आरंभ होने के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष की सर्वाधिक संख्या थी। यह संख्या वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 51.6 प्रतिशत अधिक थी।

इस विकास का महत्व केवल स्टार्टअप की संख्या में नहीं है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र धीरे-धीरे तकनीकी सेवाओं के अलावा कृषि, चिकित्सा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और औद्योगिक समाधान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में नवाचार अब जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवाओं और सतत विकास से जुड़े समाधानों सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत हो रहा है।

5. रोजगार सृजन पर स्टार्टअप का प्रभाव

भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में श्रम बाजार में आने वाले युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती रहती है। इस संदर्भ में स्टार्टअप दो प्रकार से योगदान करते हैं। पहला, वे अपने कर्मचारियों के लिए सीधे रोजगार पैदा करते हैं। दूसरा, वे आपूर्ति श्रृंखला, वितरण, परिवहन, स्वतंत्र पेशेवर सेवाओं, डिजिटल विपणन, लॉजिस्टिक्स तथा प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार और आय के अवसर उत्पन्न करते हैं।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की सूचना थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 4.99 लाख से अधिक नए प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या लगभग 3.67 लाख थी। एक वर्ष में नए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में लगभग 36.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

यह प्रवृत्ति लंबे समय में और अधिक स्पष्ट होती है। कैलेंडर वर्ष 2017 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने लगभग 52 हजार प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज किए थे। 2022 में यह वार्षिक संख्या लगभग 2.75 लाख और 2023 में लगभग 3.92 लाख हो गई। 2025 में लगभग 4.68 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज किए गए।

इसका अर्थ यह नहीं कि स्टार्टअप भारत की बेरोजगारी समस्या का अकेले समाधान कर सकते हैं। फिर भी वे संगठित आर्थिक गतिविधियों में नए रोजगार स्रोतों का निर्माण कर रहे हैं और विशेष रूप से उच्च-कौशल, डिजिटल एवं नई तकनीक आधारित कार्यों के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं।

6. रोजगार का क्षेत्रीय स्वरूप

स्टार्टअप रोजगार के विषय में एक सामान्य धारणा है कि इसका अधिकांश भाग सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी तक सीमित है। सरकारी क्षेत्रवार आँकड़े इस धारणा को पूर्ण रूप से सही नहीं ठहराते। 31 अक्टूबर 2024 तक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा 55 से अधिक उद्योग क्षेत्रों में कुल लगभग 16.68 लाख प्रत्यक्ष रोजगार की सूचना दी गई थी।

उस समय आईटी सेवाओं में लगभग 2.04 लाख रोजगार दर्ज थे, लेकिन स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान क्षेत्र में लगभग 1.48 लाख, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक सेवाओं में लगभग 94 हजार, शिक्षा में 90 हजार से अधिक, निर्माण क्षेत्र में लगभग 88.7 हजार, खाद्य एवं पेय क्षेत्र में लगभग 88.5 हजार और मानव संसाधन क्षेत्र में लगभग 88 हजार रोजगार दर्ज थे। कृषि से संबंधित स्टार्टअप में लगभग 83 हजार प्रत्यक्ष रोजगार बताए गए थे। वित्तीय तकनीक क्षेत्र में लगभग 56.8 हजार, तकनीकी हार्डवेयर में लगभग 50.9 हजार और नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 41.5 हजार रोजगार दर्ज किए गए थे।

ये आँकड़े बताते हैं कि स्टार्टअप अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे डिजिटल सेवाओं के साथ वास्तविक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ रही है। कृषि-तकनीक स्टार्टअप किसानों को बाजार, मौसम, कृषि निवेश और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समाधान प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य स्टार्टअप दूरस्थ चिकित्सा, निदान, स्वास्थ्य डेटा और चिकित्सा उपकरणों पर कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, सौर ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन में नए समाधान विकसित कर रहे हैं।

7. रोजगार की प्रकृति में बदलाव

स्टार्टअप ने केवल रोजगार की संख्या ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि कार्य की प्रकृति में भी परिवर्तन किया है। पारंपरिक कंपनियों में कर्मचारी प्रायः निश्चित विभाग में सीमित भूमिका निभाते थे। प्रारंभिक अवस्था के स्टार्टअप में कम कर्मचारियों को कई प्रकार के कार्य करने पड़ सकते हैं। इससे तकनीकी कौशल के साथ समस्या समाधान, संचार, उत्पाद विकास, डिजिटल विपणन, डेटा विश्लेषण और व्यावसायिक निर्णय जैसी क्षमताओं की माँग बढ़ती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवाएँ, रोबोटिक्स और डेटा विज्ञान से जुड़े स्टार्टअप नए प्रकार के उच्च-कौशल रोजगार पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही ई-कॉमर्स, खाद्य वितरण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप ने बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म आधारित काम के अवसर बनाए हैं।

लेकिन रोजगार की गुणवत्ता के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टार्टअप में तेजी से विस्तार के साथ तेजी से पुनर्गठन भी होता है। पूँजी की कमी या व्यवसाय मॉडल विफल होने पर कर्मचारियों की छँटनी हो सकती है। प्लेटफॉर्म आधारित काम में रोजगार लचीलापन उपलब्ध होता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, निश्चित आय और दीर्घकालीन रोजगार सुरक्षा की समस्या हो सकती है। इसलिए स्टार्टअप रोजगार का मूल्यांकन केवल नौकरी की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि वेतन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार स्थिरता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

8. छोटे शहरों में उद्यमिता और रोजगार का प्रसार

भारत के स्टार्टअप विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका महानगरों से बाहर विस्तार है। जून 2026 के सरकारी विवरण में लगभग आधे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर-दो और टियर-तीन शहरों से संबंधित बताए गए।

इस परिवर्तन का रोजगार पर विशेष महत्व है। यदि स्टार्टअप केवल कुछ महानगरों में केंद्रित रहते हैं तो प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। छोटे शहरों में सफल स्टार्टअप विकसित होने पर स्थानीय स्तर पर इंजीनियर, प्रबंधक, डिजाइनर, विपणन कर्मचारी, तकनीशियन और सेवा प्रदाता के अवसर बढ़ सकते हैं।

31 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र में 38,660 से अधिक, कर्नाटक में 22,600 से अधिक, उत्तर प्रदेश में लगभग 21,960, दिल्ली में लगभग 21,120 और गुजरात में 19,270 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप दर्ज थे। उत्तर प्रदेश में इनसे 2.11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की सूचना दी गई थी। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा भी प्रमुख स्टार्टअप राज्यों में शामिल थे।

इससे यह संकेत मिलता है कि स्टार्टअप आधारित विकास की संभावनाएँ अब केवल पारंपरिक तकनीकी केंद्रों तक सीमित नहीं हैं।

9. महिला उद्यमिता पर प्रभाव

भारतीय स्टार्टअप व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी एक सकारात्मक परिवर्तन है। 31 मार्च 2026 तक 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक अथवा भागीदार थी। यह कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का लगभग 48 प्रतिशत था।

महिलाओं की स्टार्टअप भागीदारी के आर्थिक प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं। महिला उद्यमी स्वयं रोजगार प्राप्त करती हैं, अन्य महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करती हैं और कई बार ऐसी समस्याओं के समाधान विकसित करती हैं जिन्हें पारंपरिक बाजार पर्याप्त महत्व नहीं देता। स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य उत्पाद, वित्तीय सेवाएँ, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएँ और सामाजिक उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों की भूमिका बढ़ रही है।

हालाँकि किसी स्टार्टअप में महिला निदेशक होने और उस उद्यम का वास्तविक संचालन महिला के हाथ में होने को समान नहीं माना जा सकता। आगे की नीति में महिला संस्थापकों की पूँजी, नेतृत्व, तकनीकी संसाधन तथा बाजार तक वास्तविक पहुँच को अलग से मापना आवश्यक है।

10. नवाचार का अर्थ और स्टार्टअप की भूमिका

नवाचार का अर्थ केवल किसी नई मशीन का आविष्कार करना नहीं है। किसी मौजूदा सेवा को अधिक सस्ता, सरल, तेज और व्यापक बनाना भी नवाचार हो सकता है। भारतीय स्टार्टअप ने डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि विपणन, डिजिटल ऋण, भाषा तकनीक, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में ऐसे अनेक व्यावसायिक मॉडल विकसित किए हैं।

स्टार्टअप बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटे आकार के कारण तेजी से प्रयोग कर सकते हैं। किसी विचार के सफल न होने पर उसका संशोधन अपेक्षाकृत जल्दी किया जा सकता है। यही प्रयोगशीलता नवाचार का आधार है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भी उल्लेख किया है कि भारत में उद्यमिता और नवाचार गतिविधि अब अधिक व्यापक हो रही है तथा जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवाओं और टिकाऊ तकनीकी समाधानों तक फैल रही है।

11. वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की प्रगति

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि के साथ भारत की वैश्विक नवाचार स्थिति में भी सुधार हुआ है। WIPO के Global Innovation Index 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा। वर्ष 2020 में भारत 48वें, 2021 में 46वें और 2022 में 40वें स्थान पर था। 2024 में भारत 39वें स्थान पर था, जिससे 2025 में एक और स्थान का सुधार हुआ।

भारत निम्न-मध्यम आय समूह की 37 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम और मध्य एवं दक्षिणी एशिया की दस अर्थव्यवस्थाओं में भी प्रथम स्थान पर रहा। विशेष रूप से भारत के नवाचार परिणाम उसके नवाचार निवेश की तुलना में बेहतर पाए गए। 2025 में नवाचार इनपुट में भारत 52वें स्थान पर था, जबकि नवाचार आउटपुट में 32वें स्थान पर रहा।

इससे यह संकेत मिलता है कि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में भारत ज्ञान और तकनीक आधारित परिणाम उत्पन्न करने में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन कमजोर नवाचार इनपुट भविष्य की एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है।

12. भारतीय नवाचार समूहों का वैश्विक उभार

WIPO के 2025 नवाचार समूह विश्लेषण में भारत के चार समूह विश्व के शीर्ष 100 नवाचार समूहों में सम्मिलित हुए। इनमें बेंगलुरु 21वें, दिल्ली 26वें, मुंबई 46वें और चेन्नई 84वें स्थान पर रहे।

बेंगलुरु की विशेषता तकनीकी कंपनियों, शोध संस्थानों, इंजीनियरिंग प्रतिभा और जोखिम पूँजी के संयोजन में है। WIPO के अनुसार बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला नवाचार समूह है और वहाँ डिजिटल संचार तथा कंप्यूटर तकनीक से संबंधित पेटेंट गतिविधि उल्लेखनीय है।

इन समूहों का विकास यह दर्शाता है कि नवाचार केवल प्रयोगशाला की गतिविधि नहीं है। जब विश्वविद्यालय, शोधकर्ता, स्टार्टअप, स्थापित कंपनियाँ, निवेशक और कुशल श्रमिक एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य करते हैं, तो नए विचारों का व्यावसायीकरण अधिक तेजी से हो सकता है।

13. पेटेंट और बौद्धिक संपदा में स्टार्टअप का योगदान

नवाचार की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत पेटेंट गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक स्टार्टअप द्वारा कुल 19,400 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए जा चुके थे। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टार्टअप द्वारा 4,480 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए, जबकि 2024-25 में यह संख्या लगभग 2,850 थी।

देश में समग्र भारतीय पेटेंट गतिविधि भी बढ़ी है। भारतीय नागरिकों द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या 2020-21 में 24,326 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 68,176 हो गई। पाँच वर्षों में भारतीय नागरिकों की पेटेंट फाइलिंग में लगभग 180 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

Startup India के अंतर्गत स्टार्टअप के पेटेंट आवेदनों के लिए तीव्र परीक्षण, अधिकृत सुविधाकर्ताओं की सहायता और सामान्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट आवेदन शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। सरकार सुविधाकर्ता की लागत वहन करती है।

ये प्रावधान विशेष रूप से शुरुआती स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पेटेंट प्रक्रिया की लागत छोटी कंपनी के लिए अपेक्षाकृत अधिक बोझ हो सकती है।

14. सरकारी वित्तीय सहायता और नवाचार

स्टार्टअप के प्रारंभिक वर्षों में सबसे बड़ी कठिनाई पूँजी प्राप्त करना होती है। नए उद्यम के पास पर्याप्त संपत्ति, पुराना वित्तीय रिकॉर्ड या सुनिश्चित आय नहीं होती, इसलिए पारंपरिक बैंक वित्त हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता।

सरकार ने Fund of Funds for Startups, Startup India Seed Fund Scheme और Credit Guarantee Scheme for Startups जैसी व्यवस्थाएँ विकसित की हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक Fund of Funds के अंतर्गत 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश कोषों को ₹7,000 करोड़ से अधिक वितरित किए गए थे। इन कोषों ने आगे 1,420 से अधिक स्टार्टअप में ₹26,900 करोड़ से अधिक निवेश किया।

Startup India Seed Fund Scheme के ₹945 करोड़ के कोष के अंतर्गत 219 इनक्यूबेटर चुने गए और 3,400 से अधिक स्टार्टअप के लिए ₹605 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

यह सहायता विशेष रूप से उन नवाचारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो शुरुआती अवस्था में निजी निवेशकों को अत्यधिक जोखिमपूर्ण लगते हैं।

15. सरकारी खरीद से नवाचार को बाजार उपलब्ध होना

नवाचार तभी आर्थिक मूल्य उत्पन्न करता है जब उसके लिए बाजार उपलब्ध हो। इस दिशा में Government e-Marketplace ने स्टार्टअप को सरकारी खरीदारों तक पहुँच उपलब्ध कराने का एक माध्यम प्रदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 38,600 से अधिक स्टार्टअप GeM से जुड़ चुके थे। इसी वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप को लगभग 1.40 लाख सरकारी आदेश मिले जिनका कुल मूल्य ₹19,190 करोड़ से अधिक था।

इस व्यवस्था का महत्व केवल राजस्व प्राप्ति तक सीमित नहीं है। सरकारी संस्थान यदि नवीन भारतीय उत्पादों और तकनीकों के शुरुआती ग्राहक बनते हैं तो स्टार्टअप को अपने उत्पाद का परीक्षण, सुधार और विस्तार करने का अवसर मिलता है।

16. विश्वविद्यालय, अनुसंधान और स्टार्टअप

भारत में दीर्घकालीन नवाचार के लिए विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और स्टार्टअप के बीच मजबूत संबंध आवश्यक हैं। अनेक सफल तकनीकी अर्थव्यवस्थाओं में विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान नहीं बल्कि नए ज्ञान, पेटेंट और कंपनियों के स्रोत होते हैं।

भारत में इनक्यूबेशन केंद्र, अटल इनोवेशन मिशन, जैव प्रौद्योगिकी आधारित इनक्यूबेटर, विश्वविद्यालय नवाचार केंद्र और अनुसंधान फाउंडेशन इस संबंध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने प्रयोगशाला में विकसित तकनीक और व्यावसायिक उत्पाद के बीच की दूरी कम करने के लिए साझा Translational Research Centres जैसे ढाँचों की आवश्यकता पर बल दिया है।

यदि विश्वविद्यालय में विकसित शोध स्टार्टअप के माध्यम से बाजार तक पहुँचता है तो उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की संभावना बढ़ जाती है। इससे शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए भी पारंपरिक नौकरी के अतिरिक्त उद्यमिता का विकल्प विकसित होता है।

17. अनुसंधान एवं विकास की चुनौती

भारत ने नवाचार में प्रगति की है, किंतु अनुसंधान और विकास पर कम व्यय एक महत्वपूर्ण कमजोरी बना हुआ है। WIPO ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अनुसंधान एवं विकास व्यय को लगभग 0.65 प्रतिशत के आसपास बताया है और इसे नवाचार क्षमता की चुनौतियों में गिना है। केवल ऐप, डिजिटल व्यापार मॉडल और सेवा नवाचार के माध्यम से भारत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व प्राप्त नहीं कर सकता। सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी, नई औषधियाँ, अंतरिक्ष तकनीक, ऊर्जा भंडारण और औद्योगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में कई वर्षों तक लगातार अनुसंधान निवेश की आवश्यकता होती है।

इसलिए भारत के अगले चरण का स्टार्टअप विकास “जल्दी बढ़ने” वाले डिजिटल व्यवसायों के साथ गहरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित स्टार्टअप के विकास पर भी केंद्रित होना चाहिए।

18. स्टार्टअप अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ना सफलता का एक संकेत है, लेकिन प्रत्येक स्टार्टअप सफल नहीं होता। 31 अक्टूबर 2025 तक 1,97,692 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 6,385 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार बंद, भंग अथवा रजिस्टर से हटाई गई इकाइयों की श्रेणी में रखा गया था। यह तथ्य स्टार्टअप अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अनिश्चितता की याद दिलाता है।

दूसरी चुनौती वित्तीय पूँजी की भौगोलिक असमानता है। स्टार्टअप छोटे शहरों में बढ़े हैं, लेकिन बड़े निवेशक और जोखिम पूँजी अभी भी प्रमुख महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक केंद्रित हैं।

तीसरी चुनौती कौशल-अंतर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट तकनीकी कौशल चाहिए। शिक्षा प्रणाली और उद्योग की माँग के बीच अंतर रहने पर स्टार्टअप को प्रतिभाशाली कर्मचारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

चौथी चुनौती रोजगार स्थिरता है। निवेश उपलब्ध न होने या व्यवसाय रणनीति बदलने पर स्टार्टअप बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छुट्टी कर सकते हैं। इस कारण रोजगार सृजन के साथ रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा का भी अध्ययन आवश्यक है।

पाँचवीं चुनौती नवाचार की गुणवत्ता है। प्रत्येक नई कंपनी नवाचार नहीं करती और प्रत्येक पेटेंट व्यावसायिक रूप से मूल्यवान नहीं होता। इसलिए नीतिगत सफलता का मूल्यांकन केवल स्टार्टअप पंजीकरण, निवेश राशि या पेटेंट संख्या से नहीं, बल्कि उत्पादकता, निर्यात, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रभाव जैसे परिणामों से भी किया जाना चाहिए।

19. रोजगार और नवाचार बढ़ाने के लिए नीतिगत सुझाव

भारत में स्टार्टअप के अगले चरण में संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता और स्थायित्व पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच संयुक्त अनुसंधान बढ़ाकर विद्यार्थियों को प्रयोगशाला से बाजार तक की प्रक्रिया समझानी चाहिए। डीप-टेक स्टार्टअप को लंबी अवधि की जोखिम पूँजी और साझा अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

टियर-दो और टियर-तीन शहरों में केवल स्टार्टअप पंजीकरण बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। वहाँ इनक्यूबेटर, अनुसंधान प्रयोगशालाएँ, प्रशिक्षित मार्गदर्शक, निवेशक नेटवर्क और बाजार संपर्क भी विकसित करने होंगे।

स्टार्टअप द्वारा सृजित रोजगार को मापने के लिए अधिक मजबूत और नियमित आँकड़ा प्रणाली विकसित होनी चाहिए। प्रत्यक्ष कर्मचारियों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों, संविदा कर्मचारियों और अप्रत्यक्ष रोजगार को अलग-अलग श्रेणियों में मापा जाना चाहिए। इससे स्टार्टअप के वास्तविक श्रम-बाजार प्रभाव का अधिक विश्वसनीय आकलन किया जा सकेगा।

महिला उद्यमियों के लिए केवल स्टार्टअप में महिला निदेशक की संख्या देखने के बजाय महिला संस्थापकों को प्राप्त निवेश, व्यवसाय के आकार, रोजगार और बाजार विस्तार को भी मापा जाना चाहिए।

पेटेंट सहायता के साथ पेटेंट के व्यावसायीकरण पर जोर देना आवश्यक है। किसी विश्वविद्यालय या स्टार्टअप द्वारा पेटेंट प्राप्त करना तभी अधिक उपयोगी है जब उससे उत्पाद, तकनीकी लाइसेंस, नई कंपनी या औद्योगिक प्रक्रिया विकसित हो।

20. अध्ययन की सीमाएँ

इस अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि स्टार्टअप रोजगार संबंधी सरकारी आँकड़ों का बड़ा हिस्सा कंपनियों द्वारा स्वयं दी गई सूचनाओं पर आधारित है। इसलिए 23.36 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के आँकड़े को श्रम बाजार सर्वेक्षण से प्राप्त स्वतंत्र रूप से सत्यापित रोजगार संख्या के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी ओर, वर्तमान राष्ट्रीय आँकड़ों में स्टार्टअप द्वारा उत्पन्न अप्रत्यक्ष रोजगार को पूर्ण रूप से मापना कठिन है। किसी ई-कॉमर्स स्टार्टअप द्वारा उत्पन्न डिलीवरी, पैकेजिंग, परिवहन अथवा स्थानीय विक्रेता की अतिरिक्त आय का पूरा प्रभाव प्रत्यक्ष रोजगार आँकड़ों में शामिल नहीं होता।

इसी प्रकार Global Innovation Index संपूर्ण राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मापता है। भारत की रैंकिंग में सुधार को केवल Startup India कार्यक्रम का परिणाम नहीं माना जा सकता; इसमें विश्वविद्यालयों, स्थापित उद्योगों, डिजिटल अवसंरचना, अनुसंधान संस्थानों और व्यापक आर्थिक नीतियों का भी योगदान है।

21. निष्कर्ष

भारत की स्टार्टअप अर्थव्यवस्था पिछले दस वर्षों में प्रयोगात्मक उद्यमिता से निकलकर अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। 31 मार्च 2026 तक 2.23 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और उनके द्वारा सूचित 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार इस परिवर्तन के पैमाने को प्रदर्शित करते हैं। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता और लगभग 4.99 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

स्टार्टअप का रोजगार प्रभाव आईटी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खाद्य, निर्माण, वित्तीय तकनीक, हरित ऊर्जा और तकनीकी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में भी नई नौकरियाँ उत्पन्न हुई हैं। छोटे शहरों में स्टार्टअप का प्रसार और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस परिवर्तन को अधिक समावेशी बनाने की संभावना प्रस्तुत करती है।

नवाचार की दृष्टि से भारत का 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वें स्थान तक पहुँचना, चार भारतीय नवाचार समूहों का विश्व के शीर्ष 100 में शामिल होना और स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की बढ़ती संख्या सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन भारत का नवाचार इनपुट में 52वाँ स्थान और अनुसंधान एवं विकास पर अपेक्षाकृत कम व्यय बताता है कि आगे का मार्ग केवल स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने से पूरा नहीं होगा।

भारत को भविष्य में ऐसे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जो वास्तविक समस्याओं का समाधान करे, उत्पादक रोजगार उत्पन्न करे, भारतीय अनुसंधान को बाजार तक पहुँचाए, नई तकनीकों का स्वदेशी विकास करे और महानगरों से बाहर नवाचार क्षमता विकसित करे।

अतः स्टार्टअप को केवल तेजी से मूल्यांकन प्राप्त करने वाली कंपनियों अथवा “यूनिคอร์न” की संख्या के आधार पर देखने के बजाय रोजगार, उत्पादकता, अनुसंधान, पेटेंट के व्यावसायीकरण, निर्यात, सामाजिक प्रभाव और दीर्घकालीन व्यवसाय स्थिरता के आधार पर देखना अधिक उपयुक्त होगा। यदि भारत पूँजी, कौशल, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा और क्षेत्रीय नवाचार में मौजूद कमियों को दूर करता है, तो स्टार्टअप अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में न केवल रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकती है, बल्कि भारत को तकनीक के उपभोक्ता से वैश्विक नवाचार के प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ

1. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। (2026)। स्टार्टअप इंडिया: मान्यता, रोजगार, फंडिंग और इनोवेशन के आँकड़े। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

2. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। (2025)। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और विभिन्न उद्योगों में रोजगार। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
3. भारत सरकार। (2026)। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: उद्योग की अगली छलांग—संरचनात्मक बदलाव और वैश्विक एकीकरण। वित्त मंत्रालय।
4. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। (2025)। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025: भारत। जिनेवा: WIPO।
5. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। (2025)। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025: इनोवेशन क्लस्टर रैंकिंग। जिनेवा: WIPO।
6. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। (2025)। बेंगलुरु इनोवेशन क्लस्टर प्रोफाइल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025।
7. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। (2025)। भारत में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में तेजी। भारत सरकार।
8. स्टार्टअप इंडिया। (2026)। स्टार्टअप इंडिया योजना और बौद्धिक संपदा अधिकार सहायता। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग।
9. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। (2026)। स्टार्टअप इंडिया ने 2.23 लाख से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी और रोजगार पैदा किए। भारत सरकार।
10. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। (2026)। स्टार्टअप इंडिया: उद्यमिता, रोजगार और क्षेत्रीय विस्तार। भारत सरकार।
11. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। (2025)। DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और बंद हो चुकी इकाइयों की स्थिति। भारत सरकार।
12. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। (2025)। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के नतीजे। जिनेवा: WIPO।
13. भारत सरकार। (2026)। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: इनोवेशन, रिसर्च और औद्योगिक बदलाव। वित्त मंत्रालय।
14. स्टार्टअप इंडिया। (2026)। स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा को आसान बनाने की योजना। DPIIT, भारत सरकार।
15. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। (2026)। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स, सीड फंड और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत फंडिंग सहायता। भारत सरकार।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.